

(31) /  
प्रेषक,

धर्मन्द्र सिंह अधिकारी,  
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में

महाअधिवक्ता,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग: 1

देहरादून : दिनांक 30 नवम्बर, 2012

विषय : मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु अधिवक्ता आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समुख अंकित पद पर 01 वर्ष के लिए आबद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	आवेदक का नाम	पद
1	श्री सुधीर कुमार चौधरी	अपर शासकीय अधिवक्ता
2	श्री प्रेम सिंह सौन	सहायक शासकीय अधिवक्ता
3	श्री करन आनन्द	ब्रीफ होल्डर
4	सुश्री शिवाली जोशी	ब्रीफ होल्डर

2- उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं। क्र०सं० 1 व 2 पर उल्लिखित आबद्ध अधिवक्ता अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे। आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे।

3- कृपया उक्त अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तदनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4- उक्त आबद्ध अधिवक्तागण को न्याय विभाग के शासनादेश संख्या-67/XXXVI(1)/2010-43-एक(1)/03 दिनांक 25-03-2010 के अनुसार फीस देय होगी।

5- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

6— सम्बन्धित अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

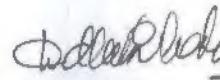
भवदीय,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)  
संयुक्त सचिव

संख्या— २७६ (१) / XXXVI(1)/2012-75 / 2007-टी०सी० तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मा० मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 2— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफीसर/निजी सचिव।
- 3— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 4— महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7— मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 8— सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 9— गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

  
(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)  
संयुक्त सचिव